

लोफतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 51 ● भिलाई, शनिवार 23 अगस्त 2025 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य – 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

संक्षिप्त समाचार

जम्मू-कश्मीर में जासूस कबूतर के पकड़े जाने के बाद स्टेशन और आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में एक जासूस कबूतर पकड़ा गया है, जिसके पैर में एक धमकी भरा नोट बंधा हुआ था। नोट में जम्मू स्टेशन को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से उड़ाने की धमकी लिखी थी। धमकी भरा नोट मिलने के बाद भारत-पाकिस्तान सीमा के पास स्थित जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर सख्ती बढ़ा दी गई है। साथ ही अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी अलर्ट घोषित किया गया है। अधिकारी कबूतर के सीमा पार पहुंचने की जांच कर रहे हैं। कबूतर को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने जम्मू से लगभग 40 किलोमीटर दूर आरएस पुरा सेक्टर के खटमारिया इलाके में पकड़ा है। नोट को उर्दू और अंग्रेजी भाषा में लिया गया था। उर्दू में लिखा था, कश्मीर हमारा है, समय आ गया है, आएगा, जबकि अंग्रेजी में लिखा था।

महाराष्ट्र के यवतमाल में रेलवे पुल के लिए खोदा गया गड्ढा बारिश से भरा, 4 बच्चे डूबे

मुंबई। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां रेलवे के एक निर्माणाधीन स्थल पर बारिश का पानी भर गया, जिसमें 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। घटना दारुव्हा रेलवे स्टेशन परिसर में हुई है, जहां महत्वाकांक्षी वर्धा-यवतमाल-नांदेड़ परियोजना के तहत रेलवे पुल बनाया जा रहा है, जिसके लिए गड्ढे खोदे गए हैं। मृतक बच्चों में रेहान खान (13), गोल्ड नारनवरे (10), सौम्या खडसन (10) और वैभव बोधले (14) हैं, जो दारुव्हा के निवासी थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, परियोजना के तहत पुल बनाने के लिए कई गहरे गड्ढे खोदे गए हैं, जिसमें पिछले 5 दिन से हो रही बारिश के कारण पानी भर गया था। निर्माण स्थल के आसपास कोई बैरिकेड या घेराव नहीं बनाया गया था, जिससे बच्चों का समूह उसमें नहाने के लिए उतर गया। बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वे वहीं बेहोश हो गए। इसके बाद उनकी डूबने से मौत हो गई।

अहमदाबाद में छात्र को चाकू मारने वाले आरोपी की दोस्त से बातचीत आई सामने, कोई पछतावा नहीं

अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में 10वीं के छात्र नयन को चाकू मारने वाले 8वीं के छात्र में घटना को लेकर कोई पछतावा नहीं है। यह खुलासा उसकी बातचीत से हुआ है। आरोपी छात्र ने वारदात के बाद अपने एक दोस्त से मोबाइल पर चैटिंग की, जिसमें उसने कहा कि अब जो हो गया, वो बीत गया है। आरोपी छात्र ने बातचीत में चाकू मारने की बात भी कबूल की है। आरोपी को उसके एक दोस्त ने मोबाइल पर संदेश भेजा कि क्या उसने आज स्कूल में कुछ किया है। इस पर आरोपी ने हां में जवाब दिया। दोस्त ने बताया कि जिस लड़के को उसने मारा है, वह मर चुका है।

तृणमूल कांग्रेस पर पीएम मोदी का करारा हमला

केंद्र का पैसा जनता तक नहीं टीएमसी के पास जा रहा...

कोलकाता/ एजेंसी

पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में विभिन्न मेट्रो रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से नोआपाड़ा-जय हिंद विमानबंदर मेट्रो सेवा और सियालदह-एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही मोदी ने मेट्रो की सवारी की और मेट्रो परियोजनाओं में शामिल स्कूली छात्रों और निर्माण श्रमिकों से बातचीत की। इस दौरान मोदी ने कहा कि आज एक बार फिर मुझे पश्चिम बंगाल में विकास को गति देने का अवसर मिला... सभी कि कोलकाता के सार्वजनिक परिवहन में प्रगति हुई है... में इन

विकास परियोजनाओं के लिए कोलकाता के लोगों को बधाई देता हूं। वहीं, कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं ऐसे समय में आया हूं जब दुर्गा पूजा की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। बड़ा बाजार से लेकर पार्क स्टीट तक, कोलकाता इस उत्सव की तैयारी और सजावट में व्यस्त है। खुशी और आस्था के इस उत्सव में जब विकास का उत्सव भी जुड़ जाता है, तो खुशी दोगुनी हो जाती है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। इसलिए जब तक पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा, तब तक विकसित भारत की यात्रा सफल नहीं हो पाएगी। क्योंकि भाजपा मानती है, भाजपा की



श्रद्धा है - जब बंगाल का उदय होगा, तभी विकसित भारत बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में केंद्र की बीजेपी सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए लगातार हर प्रकार की मदद दी है। बंगाल में नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए जितना पैसा कांग्रेस की

यूपीए सरकार ने अपने 10 साल में दिया था। उससे 3 गुना से ज्यादा पैसा हमारी भारत सरकार ने बंगाल को दिया है। रेलवे के लिए भी बंगाल का बजट पहले की तुलना में तीन गुना बढ़ाया गया है। लेकिन, बंगाल में विकास कार्यों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती

है। चुनौती ये कि बंगाल के लिए जो पैसा हम राज्य सरकार को सीधे भेजते हैं...उसका ज्यादातर हिस्सा यहां लूट लिया जाता है। वो पैसा टीएमसी काइड पर खर्च होता है। इसलिए गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं में बंगाल... देश के दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ है। मोदी ने कहा कि कुछ साल पहले पड़ोस में असम और त्रिपुरा के भी यही हाल थे। लेकिन जबसे असम और त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनी है, गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ वहां जनता को मिलने लगा है। आज इन राज्यों में हर घर जल का काम तेजी से चल रहा है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज हर गरीब को मिल रहा है। गरीबों के पक्के घर बन रहे हैं।

कोलकाता भारत के इतिहास और भविष्य की समृद्ध पहचान

अपने संबोधन के शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘कोलकाता जैसे हमारे शहर भारत के इतिहास और हमारे भविष्य दोनों की समृद्ध पहचान है। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है तब दमदम, कोलकाता इन शहरों की भूमिका बहुत बड़ी है... ये आयोजन इस बात का प्रमाण है कि आज का भारत अपने शहरों का कैसे कायाकल्प कर रहा है। उन्होंने मेट्रो सेवा को लेकर कहा कि 2014 से पहले देश में सिर्फ 250 किलोमीटर मेट्रो रूट था, आज देश में मेट्रो रूट बढ़कर 1,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है।

गांधीनगर में हुई नारेबाजी

सीएम रेखा के कार्यक्रम में फिर से हंगामा हुआ..

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में फिर से हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि अशोक बाजार गांधी नगर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता थोक रेडीमेड गारमेंट डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित वक्त्रिका 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थीं। एक शख्स यहां नारेबाजी कर हंगामा कर रहा था। जिसे बैरिकेडिंग के बाहर ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वहीं, जानकारी मिली है कि एक अन्य शख्स को भी हंगामा करने के संदेह में पकड़ा गया है। जनसुनवाई में मुख्यमंत्री पर हुए हमले के बाद रेखा गुप्ता पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में



शामिल होने के लिए घर से बाहर निकली थीं। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद हर्ष मल्होत्रा, स्थानीय विधायक अरविंद सिंह लवली, पार्षद और गांधीनगर मार्केट के तमाम व्यापारी मौजूद रहे। इस हंगामे से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा।

ऑनलाइन गेमिंग बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी

बना कानून, जेल और एक करोड़ रूपए जुर्माने का होगा प्रावधान...

नई दिल्ली/ एजेंसी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसे एक दिन पहले राज्यसभा ने पारित किया था। यह कानून सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाता है और सुविधा प्रदान करने वालों के लिए तीन साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करता है। ऐसे प्लेटफॉर्म का विज्ञापन करने पर दो साल तक की सजा और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उच्च सदन ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं



विनियमन विधेयक, 2025 को 26 मिनट में पारित कर दिया। इससे एक दिन पहले लोकसभा ने प्रक्रियागत चिंताओं को लेकर विषय के विरोध के बीच इसे सात मिनट में पारित कर दिया था। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में सांसदों

को बताया कि लोग ऑनलाइन मनी गेमिंग में अपनी जीवन भर की जमा-पूँजी गंवा रहे हैं। वैष्णव ने राज्यसभा में कहा कि समय-समय पर समाज सामाजिक बुराइयों से जूझता है। ऐसे में सरकार और संसद का यह कर्तव्य है कि वे इनकी जाँच करें और इन्हें नियंत्रित करने के लिए कानून बनाएँ। मंत्री ने कहा, “जब समाज और सरकार के राजस्व के बारे में चिंता करनी होती है तो इन दोनों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा मध्यम वर्गीय परिवार (के कल्याण) को ही चुना है, हमेशा समाज के फायदे को ही चुना है, कभी इससे समझौता नहीं किया है। और इस विधेयक में भी समाज के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है।

दिल्ली के 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, लगातार तीसरे दिन आया ईमेल

नईदिल्ली। दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलना बंद नहीं हो रही है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी दी गई है, जिसमें प्रसाद नगर और द्वारका सेक्टर 5 समेत अन्य इलाकों के 5 स्कूल शामिल हैं। धमकी की सूचना पर दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता, डॉग स्कॉयड और अग्निशमन दल के साथ मौके पर पहुंच गया है। जांच जारी है। सुबह 5 स्कूलों को ईमेल मिलने से पहले बुधवार को करीब 50 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी थी। सभी स्कूलों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद स्कूल खाली कराए गए।

एनडीए की होगी जीत

न राहुल गांधी पीएम बनेंगे...न उदयनिधि सीएम-अमित शाह

नई दिल्ली/ एजेंसी

तमिलनाडु चुनाव को लेकर भाजपा अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्य में बृथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन के शुरूआत में कहा कि मैं राज्य के लोगों को यह बताने आया हूँ कि उपराष्ट्रपति का पद संभालने के बाद, तमिलनाडु का बेटा सीपी राधाकृष्णन राज्यसभा का सभापति बनने जा रहा है। इससे पहले एनडीए ने एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी भारत का राष्ट्रपति बनाकर यह सम्मान दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा तमिलनाडु,



तमिल भाषा और तमिल संस्कृति को गौरवान्वित करने का काम किया है। शाह ने कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने प्रतिष्ठित तमिल नेता सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति जैसे प्रतिष्ठित पद के लिए

नामित किया है। इसके बाद शाह ने कहा कि पहलगाम में, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने निर्दोष नागरिकों की दुखद जान ले ली। मोदी जी ने देश को दुद्र्ता से आश्रस्त किया कि आतंकवादियों और उनके कृत्यों को अंजाम देने वालों, दोनों को परिणाम भुगतने होंगे। ऑपरेशन सिंदूर को अधिकृत करके, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान में गहराई तक स्थित आतंकवादी ठिकाने नष्ट कर दिए जाएँ। इसके अलावा, ऑपरेशन महादेव ने पहलगाम में हुए जघन्य हमले के लिए जिम्मेदार तीन आतंकवादियों को सफ़तापूर्वक मार गिराया।

सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को बड़ा आदेश

बिहार एसआईआर में आधार कार्ड या 11 अन्य दस्तावेज मान्य

नई दिल्ली/ एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावी राज्य बिहार में चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में बदलाव करने से इनकार कर दिया, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को निर्देश दिया कि वह सूची से बाहर किए गए मतदाताओं को ऑनलाइन माध्यम से दावे दाखिल करने की अनुमति दे, साथ ही भौतिक रूप से भी दावा पेश करने की अनुमति दे। अदालत ने निर्वाचन आयोग को मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए 11 दस्तावेजों या आधार कार्ड को स्वीकार करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की दो सदस्यीय पीठ

ने राजनीतिक दलों को उन 65 लाख लोगों की मदद करने का भी निर्देश दिया, जिन्हें मसौदा मतदाता सूची से बाहर रखा गया है। अदालत ने कहा, सभी राजनीतिक दल अगली सुनवाई तक उस दावा प्रपत्र पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे उन्होंने बहिष्कृत मतदाताओं द्वारा दाखिल करने में मदद की थी। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि केवल दो आपत्तियाँ उठाई गईं, जबकि राजनीतिक दलों के 1.60 लाख से अधिक बूथ-स्तरीय एजेंट (बीएलए) हैं। सुनवाई के दौरान, चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि उसे यह सख्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए कि कोई



भी मतदाता सूची से बाहर नहीं है। आयोग ने अदालत को यह भी बताया कि 85,000 बहिष्कृत मतदाताओं ने अपने दावा पत्र जमा कर दिए हैं, जबकि दो लाख से ज्यादा नए मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए

आगे आए हैं। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिकता राकेश द्विवेदी ने अदालत से कहा, राजनीतिक दल शोर मचा रहे हैं और हालात इतने खराब नहीं हैं। हम पर विश्वास रखें और हमें कुछ और समय दें। हम आपको दिखा देंगे

कि कोई भी मतदाता सूची से बाहर नहीं है। बिहार में जहाँ इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर अभियान चलाने के फैसले से भारी राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। एसआईआर के अनुसार, बिहार में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या इस अभियान से पहले के 7.24 करोड़ से घटकर 7.9 करोड़ रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी व्यक्ति खुद से या राजनीतिक पार्टियों के बृथ लेवल एजेंट्स की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और उन्हें भौतिक तौर पर फर्म जमा करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि आवेदन में फर्म 6 के साथ आवेदक आधार कार्ड समेत 11 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज जमा कर सकता है।

अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी

पीठ ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को अगली सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसमें उन्हें बताना होगा कि उन्होंने कितने लोगों की ऑनलाइन फॉर्म भरने में मदद की। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई अब 8 सितंबर को तय की है। पीठ ने चुनाव अधिकारियों से ये भी कहा कि बृथ लेवल एजेंट्स द्वारा आवेदन कराए जाने पर उन्हें एक पृथी भी दी जाए। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिकता राकेश द्विवेदी ने अदालत से अग्रह किया कि चुनाव आयोग को यह सख्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए कि कोई भी मतदाता सूची से बाहर नहीं है। द्विवेदी ने कहा, ‘राजनीतिक दल शोर मचा रहे हैं, लेकिन स्थिति उतनी खराब नहीं है। हम पर विश्वास रखें और हमें कुछ और समय दें। हम आपको दिखा देंगे कि कोई भी मतदाता सूची से बाहर नहीं है।

महोदय के संज्ञान में मामला लाकर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

प्रष्ट संचालकों एवं ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। पोर्टल पर दर्ज पंजीयन एवं आवेदन की स्वीकृति/निस्तीकरण की जानकारी भी रैडम आधार पर जांची जाएगी।

पंजीयन एवं योजना आवेदन की स्थिति से जुड़ी शिकायतों का त्वरित निराकरण होगा। श्रमिकों/हितग्राहियों को श्रमवै जयते मोबाइल एप का माध्यम से जारूक किया जाएगा।

सभी श्रम कार्यालयों एवं श्रम संस्थानों से श्रमिकों को ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। श्रमावुक्त कार्यालय ने साफ किया है कि श्रमिकों के हितों की रक्षा एवं पारदर्शीता सुनिश्चित करने के लिए तय सीमा से अधिक शुल्क लेने वाले सीएससी संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संपादकीय

कई शहरों में एक-दो घंटे की बरसात में ही सब कुछ ठहर-सा जाता है और चारों ओर बाढ़ का दृश्य बन जाता है। यह निश्चिंत रूप से अनियोजित शहरी विकास का नतीजा नहीं है, जहाँ बाढ़ अच्छी सड़कों तो बना दी जाती है, लेकिन पानी के निकास का उचित और पर्याप्त इंतजाम नहीं किया जाता है। मौसम की अपनी गति होती है और सामान्यतः स्थितियों में वह पारिस्थितिकी चक्र को बनाए रखने का एक जरूरी हिस्सा होती है। मगर पिछले कुछ समय में इसके स्वरूप में तेजी से बदलाव दर्ज किया जा रहा है और

समूची दुनिया में मौसम के बिगड़ते स्वरूप को लेकर जताई जा रही है चिंता

खासतौर पर बारिश की वजह से होने वाली तबाही की ओर दृष्टि रखते हुए ज्योदा बिगड़ती जा रही है। दोहरे वर्ष मानसून के पूर्ण मौसम में बारिश की वजह से देश के ज्यादातर हिस्से कमजोर हो चुके हैं। ज्योदा प्रभावित होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि बरसात अब बेलगाम हो रही है और तबाही कासातिलसिला-सा बनता जा रहा है। पिछले दिनों उत्तराखंड के धराली और हरिद्वार में, फिर जम्मू-कश्मीर के तिरवाड़ी में तबाही बढते बढते आये उससे हुई जानमाल की भारी तबाही को देखें जैसी घटनाएं हुई, उन्होंने देश के बाह्य हिस्सों के लोगों को नारा

भी दहला दिया। अब कश्मीर के कटुआ में भी बादल फटने लगे और भूखलन की घटना में सात लोगों की जान चली गई। दूसरी ओर, मुंबई में लगातार तीन दिन की बारिश के बाद हालत यह हो गई, मानो शहर में बाढ़ आ गई हो। यहां कई इलाकों में जलभराव की वजह से जनजीवन पूरी तरह बाधित हो गया, कई जिलों में चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं मराठवाड़ा क्षेत्र में बादल फटने की घटना में नांदेड़ के पांच लोगों के लापता होने की खबर आई। इसी तरह, हिमाचल प्रदेश के हंडी सहित कई इलाकों में जिस तरह

लगातार बार-बार बदल फटने की घटनाएँ सामने आ रही हैं, उससे समझी स्थानीय आबादी के सामने किसी तरह खुद को बचाव की चुनौती खड़ी हो रही है। यह समझना मुश्किल हो रहा है कि कम या ज्यादा बरसात वाले जिस मानसून को देश की खेती-किसानी के लिए एक जरूरत के तौर पर देखा जाता था, अब वह कई राज्यों में व्यापक तबाही का कारण क्यों बन रहा है। कई इलाकों में तेज बारिश के संयोगों बदल फटने की घटना में भी इतनी अजीब-से बदलौती क्यों देखी जा रही है? दूसरी ओर, कई शहरों में

एक-दो घंटे की बरसात में ही सब कुछ उधर-सा जाता है और चारों ओर बाढ़ का दृश्य बन जाता है। यह निश्चित रूप से अनियोजित शहरी विकास का नतीजा है, जहां बहुतांश अच्छी सड़कें तो बना दी जाती हैं, लेकिन पानी के निकास का उचित और पर्याप्त इंतजाम नहीं किया जाता है। नतीजतन, दिल्ली जैसे महानगर का बड़ा हिस्सा कुछ देर की घनघोर बरसात में ही जलभराव, सड़क जाम से त्रस्त हो जाता है और पेड़ों के गिरने से होने वाले जानमाल के नुकसान की अनेक घटनाएं सामने आती हैं।

सत्ता पक्ष जहाँ शासन संचालन और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है, वहीं विपक्ष लोकतंत्र का प्रहरी बनकर उसके हर कदम पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है, असंतोष को स्वर देता है और जनभावनाओं को दिशा देता है। लेकिन वर्तमान विपक्ष इन भूमिकाओं में नकारा साबित हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष अपनी ही बिसात पर मात खा रहा है, जिस तरह से विपक्ष और विशेषतः कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी, ईवीएम में गड़बड़ी एवं मतदाता सूचियों के विशेष गहन परीक्षण पर बेतूके एवं आधारहीन आरोप लगाये हैं, उससे संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की गरिमा एवं प्रतिष्ठा तो आहत हुई ही है, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी कठघरे में दिख रही है।

अपनी ही बिसात पर मात खा रहा है विपक्ष

(ललित गर्ग)

लोकतंत्र का सार यही है कि सत्ता और विपक्ष दोनों एक-दूसरे के पूरक हों, शत्रु नहीं। विपक्ष का केवल विरोध की राजनीति से बाहर आकर वैकल्पिक दृष्टिकोण देना होगा, और सत्ता-पक्ष को भी यह समझना होगा कि विपक्ष की आलोचना लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है।

भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह केवल संख्याओं और मतों का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवंत प्रक्रिया है जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सत्ता पक्ष जहां शासन संचालन और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है, वहीं विपक्ष लोकतंत्र का प्रहरी बनकर उसके हर कदम पर प्रश्ननिर्देश खड़ा करता है, असंतोष को स्वर देता है और जनभावनाओं को कीर्ति देता है। लेकिन वर्तमान विपक्ष इन भूमिकाओं में नकारा साबित हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष अपनी ही बिसात पर मात खा रहा है, जिस तरह से विपक्ष और विशेषतः कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी, ईवीएम में गड़बड़ी एवं मतदाता सूचियों के विरोध गहन परीक्षण पर बेतुके एवं आधारहीन आरोप लगाये हैं, उससे संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की गरिमा एवं प्रतिष्ठा तो आहत हुई ही है, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी कठघरे में दिख रही है। यह अच्छा हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस कर वोट चोरी सहित ऐसा ही बेहूदा, आधारहीन एवं गुमराह करने वाले राहुल गांधी के आरोपों का न केवल बिन्दुवार जबाब दिया, बल्कि उन्हें बेनकाब करने हुए यह भी कहा कि वे या तो अपने निराधार आरोपों के सन्दर्भ में शपथ पत्र दें या सत्ता दिनों के भीतर देश से माफी मांगें। निश्चित ही राहुल गांधी को ऐसी चेतावनी देना आवश्यक हो गया था, क्योंकि वे अपने संकीर्ण एवं स्वार्थी राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिये लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को धुंधलाने की सारी हदें पार चूके हैं।

हाल के दिनों में जिस तरह चुनाव आयोग, मतदाता सूची और वोट प्रचर को आरोपों को लेकर बहस छिड़ी है, उससे इस प्रश्न को फिर से गहराई से सोचने को बाध्य किया है कि क्या लोकतंत्र विपक्ष बेवैबुन्याद आरोप लगाते हुए अपनी भूमिका को प्रश्नों के घेरे में कब तक डालता रहेगा? विपक्ष बिना ठोस प्रमाण के बड़े आरोप लगाकर लोकतंत्राधिकार संस्थाओं की विश्वसननीयता पर प्रश्न खड़े कर देता है। क्या जनहित के नाम पर जनता के व्यापक हित से जुड़े सुधारों का विरोध करना विपक्ष का शगल बन गया है? पिछले एक दशक से विपक्ष लोकतंत्र को उसक बनाने की अपनी भूमिका की बजाय उसका कमजोर एवं जर्जर करने में जुटा है। उसने सत्ता-पक्ष को घेरने के लिये जरूरी मुद्दों को सकारामक तरीकों से उठाने की बजाय विध्वंसालमक तरीकों से विकास के जनहितकारी मुद्दों को भी विवाद का मुद्दा बनाते हुए सारी हद्दें पार

कर पार दी है। आधार को बैंक अकाउंट से जोड़ने का मामला हो। अनुच्छेद 370 को खत्म करना हो। सीएफ-एनआरसी का मामला हो या हाल में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन परीक्षण अभियान हो। विपक्ष मोदी सरकार के इन विकासमूलक सुधारों को जनहित के खिलाफ बताते हुए मुस्कुरा विरोध कर रहा है, जो लोकतंत्र को धुंधलाने की एक बड़ी साजिश प्रतीत होती है। निश्चित ही विपक्ष की इन खोजचालों में सबसे बड़ी शक्ति जिनका की आस्था की होती है। जब चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं

लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ है कि जनता और राजनीतिक दल चुनाव आयोग व अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं कर पा रहे। इसलिए न्यायपालिका की भूमिका भी अब केवल विवाद व सुलझाने की नहीं रह गई है, बल्कि लोकतंत्र के विश्वास की पुनः स्थापित करने की हो गई है, जबकि यह कार्य राजनीतिक दलों एवं चुनी हुई सरकारों का होता है।

लोकतंत्र का सार यही है कि सत्ता और विपक्ष दोनों एक-दूसरे के पूरक हों, शत्रु नहीं। विपक्ष को केवल विरोध की राजनीति से बाहर आकर

जाता है। आज भारत का विपक्ष जिस तरह संसद के ठुकराये, व्यक्तिगत हमलों, दुष्प्रचार और असंवैधानशील अचरण पर आमादा है, उसने लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुँचाई है। संसद सत्र, जहाँ जनता की समस्याओं का समाधान खोजा जाना चाहिए, वहीं विपक्ष का रवैया अवरोध पैदा करने वाला अधिक दिखता है। महत्वपूर्ण विधेयकों पर सार्थक चर्चा के बजाय नारेबाजी और वॉक-आउट आम बात हो गई है। यह स्थिति केवल सरकार ही नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए घातक है। इतिहास गवाह है कि जब-जब विपक्ष ने



को निष्पक्षता सँदिग्ध बनाई जाती है, तो लोकतंत्र की नींव हिलने लगती है। लोकतंत्र में हार-जीत से भी बड़ा मुद्दा चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता होता है।

विपक्ष केवल सत्ता की आलोचना करने के लिए नहीं है। उसका दायित्व है कि वह जनता की समस्याओं जैसे बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी की अतिशयोक्तिपूर्ण वसूली, पर्यावरण, सफाई, नारी की असुरक्षा जैसे ज्वलंत मुद्दों को उभार कर ठोस विकल्प प्रस्तुत करे और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती में योगदान दे। केवल आरोप-प्रत्यारोप में उलझकर यदि विपक्ष अपनी ऊर्जा खर्च कर देता है तो वह जनता का विश्वास खो देता है। यही कारण है कि आज विपक्ष की स्थिति कमजोर मानी जा रही है, क्योंकि वह केवल आरोप लगाता हुआ दिखता है, समाधान प्रस्तुत करने में पिछड़ जाता है। सत्ता पक्ष को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र केवल बहुमत से नहीं चलता, बल्कि समझ और पारदर्शिता से भी चलता है। यदि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष का कर्तव्य है कि वह धैर्यपूर्वक उत्तर दे, जाँच के रास्ते खोले और हार आपस की तमज्जा से परखे। विपक्ष को नकार देना लोकतंत्र को कमजोर करना है। जब सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता है, तब न्यायपालिका अंतिम सहारा बनती है। यही कारण है कि आज बार-बार सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की माँग उठती है। यह स्थिति लोकतंत्र के

वैकल्पिक दृष्टिकोण देना होगा, और सत्ता-पक्ष को भी यह समझना होगा कि विपक्ष की आलोचना लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रारंभ से ही विपक्ष को महत्व दिया है, उन्होंने संवेदनशील सरकार के साथ सृजनात्मक नेतृत्व का परिचय दिया है लेकिन विपक्ष जब आग्रह, पूर्वाग्रह एवं दुराग्रह से घिरा हो तो सरकार को दिशाएँ कैसे उद्धटित हो सकती है? आज़म की राजनीति में लोकतंत्र और विपक्ष के बीच खड़ी पतवार तेज़ है। यह टकराव लोकतंत्र को कमजोर करने वाला नहीं बल्कि उसे और परिष्कृत बनाने वाला होना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि विपक्ष अपनी रचनात्मक भूमिका निभाए और सत्ता पक्ष उसकी आलोचना को स्वीकार कर उत्तरदायित्वपूर्ण जवाब दे। तभी लोकतंत्र की असली शक्ति और जनता के विश्वास को बनाए रखना संभव है।

लोकतंत्र की शक्ति केवल सरकार में नहीं बल्कि एक सशक्त और रचनात्मक विपक्ष में भी निहित होती है। विपक्ष लोकतांत्रिक ढाँचे का आवश्यक स्तंभ है, जो सत्ता पर निगरानी रखता है, नीतियों में कमियों को उजागर करता है और जनता की आवाज को सदन तक पहुँचाता है। लेकिन जब विपक्ष अपनी इस जिम्मेदारी को भूलकर केवल नकारात्मक राजनीति पर उतर आए, तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होने लगती है और देश की छवि तथा स्थिरता पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो

रचनात्मक भूमिका निभाई है तो लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। 1977 में आपातकाल के विरोध से लेकर 1989 तक विपक्ष ने लोकतंत्र को बचाने पर पुनर्जीवित करने का कार्य किया। लेकिन 2014 के बाद से जिस तरह विपक्ष अपरिपक्व, निरंतर बिखरा हुआ, नेतृत्व रहित है, उसने नारात्मक एजेंडे पर केंद्रित नहीं है, उसने लोकतांत्रिक संस्कृति को आघात पहुंचाया है।

विदेशी लोकतंत्र हमेशा से भारत की आंतरिक कमजोरी का फायदा उठाने की निरन्तर प्रवृत्ति में रहती हैं। जब विपक्ष सरकार की नीतियों का विरोध करने के नाम पर राक्ष-विरोध, राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना की कार्रवाई या विदेश नीति तक पर सवाल उठाने लगता है, तो इसका सीधा लाभ पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को मिलता है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को धूमिल करना विपक्ष का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से हालत यही इशारा कर रहे हैं। लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद को 'घिघटन' में बदल देना खतरनाक है। विपक्ष को याद रखना होगा कि उसकी जिम्मेदारी केवल सत्ता पाने की नहीं, बल्कि देश की स्थिरता और विकास को सही दिशा देने की भी है। अगर विपक्ष अपने दायित्वों को नकारात्मक राजनीति में खोता रहा तो यह न केवल उसके लिए बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। आज समय की मांग है कि विपक्ष आत्मतन्त्र करे।

घुमन्तु समाज को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए जरूरी केंद्र व राज्य सरकारों की इच्छाशक्ति

डॉ अतुल मलिकराम (राजनीतिक रणनीतिकार)
भारत की सांस्कृतिक विविधता में घुमंतू समाज एक अनमोल रत्न की तरह है, जो अपनी अनूठी जीवनशैली और परंपराओं के साथ देश की सामाजिक-आर्थिक संरचना का अभिन्न हिस्सा रहा है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह समाज, दशकों से अपनी खानाबदोश प्रकृति के कारण मुख्यधारा से कटा हुआ है और आज भी मूलभूत सुविधाओं व अधिकारों से वंचित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों तक उनकी पहुंच बेहद सीमित है। ऐसे में सवाल उठता है कि आज हम आजादी के 80वें साल में तो प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन घुमंतू समाज के कल्याण व उथान के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाए हैं? क्या घुमंतू समाज के उथान को ध्यान में रखकर उन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता? क्या राष्ट्रीय स्तर के कॉमन आईडेंटिटी कार्ड नहीं बनाया जा सकता? क्या उनके लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर धर्मशाला जैसी अस्थायी आवास सुविधा का निर्माण नहीं किया जा सकता? ये केवल सवाल ही नहीं जवाब और सुझाव भी हैं, जिन पर केंद्र व राज्य सरकारों अमल करके, देश की लगभग 10 फीसदी आबादी को मुख्यधारा में जोड़ सकती हैं।

कई राज्यों में घुमन्तु समुदाय को लेकर बोर्ड का गठन किया गया है, सबसे अधिक जनसंख्या के लिहाज से घुमन्तु प्रदेशों का जैसे राज्य में तो अलग मंत्रालय भी है लेकिन घुमन्तुओं का जीवन स्तर जस का तस है। जन्म से ही अपारार्थिक प्रवृत्ति का घोषित कर दिए गए इस समाज के उत्थान को लेकर अब तक की सभी सरकारों ने जो कदम उठाए हैं उसकी बानगी घुमन्तुओं की वर्तमान परिस्थिति में साफ झलकता है।

घुमन्तु समाज को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए
जरूरी केंद्र व राज्य सरकारों की इच्छाशक्ति

ये समुदाय, जिन्हें बंजारा, गडिया लोहार जैसे अन्य कई शासिल हैं, अपनी आजीविका के लिए कई तरह के पारम्परिक व्यवसायों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन आधुनिकरण और शहरीकरण ने अब उनकी आजीविका का कौ भी खतरे में डाल दिया है। कुछ मॉडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि कई बार तो उन्हें अपने मृत परिवारों का अंतिमम संस्कार करने तक की जगह नहीं मिलती क्योंकि जिस गाँव

या इलाके से यह गुजर रहे होते हैं वहाँ के लोग उनके साथ उनके अछूतों जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसे में उनके साथ हमारा गुनाह समाज मानवता का कितना परिचय देता होगा, समाज जान सकता है। हालाँकि यह दुखद आंकड़े ही हमें उनके बेहतर भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित भी करते हैं।

मेरे सुझाव में घुमटू समाज को सामाजिक और शैक्षिक रूप से समेकित आबोसी की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। यह कदम

उन्हें सरकारी योजनाओं, आरक्षण, और अन्य लाभों तक पहुँच प्रदान करेगा। यह न केवल उनकी गरिमा को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर भी देगा। दूसरा उपाय उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर के कॉमन आइडेंटिटी कार्ड से जोड़कर किया जा सकता है। यह कार्ड घुमंतू समाज के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं होगा। उनकी लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के लिए यह कार्ड उन्हें कहीं से भी मतदान करने, राशन लेने, बच्चों को स्कूल भेजने, अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने और रोजगार के अवसरों को अपनाने में सक्षम बनाना सुनिश्चित कर सकता है। कम शब्दों में समझें तो यह कार्ड उनकी पहचान को एकजुट करेगा और उनके अधिकारों को सुरक्षित करेगा, चाहे वे कहीं भी हों।

इसके अलावा, राज्यों में तहसील स्तर पर धर्मशाला जैसी अस्थायी आवास सुविधा का निर्माण भी किया जा सकता है। इन स्थानों पर स्वच्छता, पेयजल, बिजली और सुरक्षा जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। यह न केवल उनके जीवन को सम्मानजनक बनाएगा, बल्कि उनकी घमकड़ी प्रकृति को भी संरक्षित रखेगा।

हमें एक आदर्श समाज का उदाहरण बनते हुए यह नहीं भूलना चाहिए कि घुमंतू समाज भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवंत हिस्सा है। उनकी अनूठी जीवनशैली को सम्मान देते हुए, हमें उद्देश्यधारा में शामिल करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। केंद्र सरकार के नेतृत्व में भारत ने सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। निश्चित तौर पर इन सुझावों को लागू कर के, घुमंतू समाज का जीवन स्तर बेहतर किया जा सकता है और भारत के समावेशी विकास के सपने को और मजबूती दी जा सकती है।

संक्षिप्त समाचार

सीरिया में वरिष्ठ इस्लामिक स्टेट सदस्य अरेस्ट

दमिश्क, एजेंसी। अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने उत्तर-पश्चिम सीरिया में इस्लामिक स्टेट (आईएस) के एक वरिष्ठ सदस्य को गिरफ्तार किया है। बुधवार को चलाए गए इस अभियान की पुष्टि सीरियाई मीडिया और एक युद्ध निगरानी संगठन ने की। अधिकारियों ने पहचान का खुलासा नहीं किया है, ऐसे में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पकड़ा गया शख्स आईएस का सर्वोच्च नेता है या कोई आम सदस्य। सूत्रों के अनुसार, इराकी नागरिक और आईएस कमांडर अबू हाफिज अल-कुरेशी को तुर्किये की सीमा के पास आतमेह करबे में हेलीकॉप्टर से उतारे सैनिकों ने पकड़ा। ब्रिटेन की संस्था- सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक, इस अभियान के दौरान एक अन्य इराकी नागरिक मारा गया। निगरानी समूह का दावा है कि गिरफ्तार शख्स के साथ फ्रेंच बोलने वाली एक महिला भी पकड़ी गई है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उसे अमेरिकी बलों ने पकड़ा या बाद में सीरियाई सुरक्षा बलों ने। सीरिया के सरकारी टीवी चैनल के मुताबिक गिरफ्तार शख्स का नाम सलाह नोमान है। वह अपने परिवार के साथ एक अपार्टमेंट में रह रहा था।

इसाइल में वेस्ट बैंक सेटलमेंट परियोजना को मंजूरी

येरुशलम, एजेंसी। इसाइल ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक बस्ती बसाने की विवादास्पद परियोजना को अंतिम मंजूरी दे दी है। परियोजना लागू होने के बाद वेस्ट बैंक दो हिस्सों में बंट सकता है। इस मामले में पलस्तनी और मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में स्वतंत्र फलस्तीनी की संभावना लाभग समाप्त हो जाएगी। बुधवार को वित्त मंत्री बेजलेल स्मोर्ट्रिच ने इस मंजूरी को पश्चिमी देशों के को इसाइल का करारा जवार बताया। स्मोर्ट्रिच ने कहा, स्वतंत्र फलस्तीन अब नारेबाजी से नहीं बल्कि ठोस कदमों से मिटाया जा रहा है। हर बस्ती, हर मोहल्ला और हर मकान इस खतरनाक विचार के ताबूत में एक और कील है। इसाइल के इस निर्णय को क्षेत्र में तनाव बढ़ाने और शांति प्रक्रिया के लिए गंभीर झटका माना जा रहा है। बता दें कि येरुशलम के पूर्व में ई1 क्षेत्र में इसाइल बस्ती विकसित करने की योजना बना रहा है। बीते दो दशकों से इस पर विचार हो रहा था, लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण अब तक इस पर कार्यान्वयन नहीं हुआ है।

कांगो और एम23 विद्रोहियों के बीच शांति समझौते की कोशिश

किंशासा, एजेंसी। कांगो सरकार और रवांडा समर्थित विद्रोही संगठन एम23 के बीच एक शांति समझौते का मसीदा तैयार हुआ है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य- उन इलाकों पर फिर से सरकारी नियंत्रण लाना है, जिन पर फिलहाल एम23 का कब्जा है। यह समझौता कतर की पहल पर तैयार किया गया है और इसमें शांति कायम करने के लिए तीन चरणों वाली प्रक्रिया का जिक्र है। आने वाले दिनों में दोनों पक्ष कतर की राजधानी दोहा में बैठकर इस मसौदे पर चर्चा करेंगे। कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसीकेदी अभी इस मसौदे से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं, बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट ने कहा कि राष्ट्रपति का मानना है कि मसीदा अभी अधूरा और असंतोषजनक है। वहीं, एम23 के नेता बर्टेंड बिसिमवा ने इस मसौदे पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि अभी उनका ध्यान युद्धविराम लागू करने और कैदियों की रिहाई पर है, जो पहले से तय किए गए दोहा घोषणापत्र का हिस्सा है।

बोलीविया में चुनाव जाएगा नया राष्ट्रपति

सूक्रे, एजेंसी। बोलीविया में नया राष्ट्रपति चुनाव जाएगा। यह चुनाव देश में लगभग 20 साल से चल रही समाजवादी सरकार से बदलाव की ओर इशारा करता है। लेकिन आखिरी समुदायों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं है कि इससे अमेजन जंगलों की कटाई, आग या प्रदूषण जैसी समस्याएं रुकेंगी। 19 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में दो नेता मध्यमार्गी रोड्रिगो पाज और दक्षिणपंथी जॉर्ज ट्टो किरोगा आमने-सामने हैं। दोनों बदलाव का वादा कर रहे हैं, लेकिन उनका आर्थिक मॉडल वही है, जिसने अब तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। अमेजन जंगल नौ देशों में फैला हुआ है और यह दुनिया की जलवायु और कार्बन संतुलन के लिए बहुत अहम है।

ट्रंप के साथ बैठक के बाद वापस आते समय पुतिन को चुकाने पड़े 2.2 करोड़ रुपये

वाशिंगटन, एजेंसी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन से जंग को लेकर संघर्षविराम पर वार्ता के लिए अलास्का का दौरा किया था। यहां ट्रंप से वार्ता से पहले भले ही उनका रेड कार्पेट स्वागत हुआ हो लेकिन वहां से वापस आना पुतिन को काफी महंगा पड़ गया। दरअसल, उन्हें वहां से वापस आते समय अपने विमानों में ईंधन भरवाना पड़ा। हद तो तब हो गई जब इसके लिए उन्हें तकरीबन 250,000 डॉलर (लगभग 2.2 करोड़ रुपये) नकद चुकाने पड़े। अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी हकीकत बताई है। उन्होंने साफ किया है कि पुतिन को ऐसा क्यों करना पड़ा।

मार्को रूबियो ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अमेरिका के लिए एक समय तीन विमानों में ईंधन भरने के लिए लगभग 250,000 डॉलर (लगभग 2.2 करोड़ रुपये) नकद भुगतान करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि यह रूस पर लागू अमेरिकी प्रतिबंधों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से जंग के चलते लागू प्रतिबंधों के कारण वे हमारी बैंकिंग प्रणाली का उपयोग नहीं कर सकते थे। ऐसे में उन्हें ईंधन के लिए नकद भुगतान करना पड़ा। रूबियो ने कहा कि अमेरिका द्वारा लागू गए प्रतिबंध अभी भी लागू हैं और उनका प्रभाव भी बना हुआ है। रूबियो ने कहा कि रूस और पुतिन को हर दिन इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि इन प्रतिबंधों ने युद्ध की दिशा नहीं बदली है।

टेक्सास के नए नक्शे को मिली मंजूरी, 2026 के मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को होगा फायदा

वाॉशिंगटन, एजेंसी। टेक्सास की विधानसभा ने राज्य के नए नक्शे को अपनी मंजूरी दे दी है। नए नक्शे से रिपब्लिकन पार्टी को फायदा होगा और पांच नई सीटों का निर्माण होगा। जिन सीटों का निर्माण होगा, वो रिपब्लिकन पार्टी के प्रभाव वाली होंगी। ऐसे में 2026 में होने वाले मध्यावधि चुनाव में सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी को इससे फायदा मिलने की उम्मीद है।

रिपब्लिकन पार्टी की बढ़ सकती है पांच सीटें : राष्ट्रपति ट्रंप ने पांच साल बाद कांग्रेस सीटों के नक्शों की समीक्षा करने की अपील की थी। माना जा रहा है कि इसका उद्देश्य रिपब्लिकन पार्टी को फायदा पहुंचाना है। टेक्सास की विधानसभा ने बुधवार को नए नक्शे को मंजूरी दी। हालांकि अभी इसे लागू करने से पहले राज्य के सीनेट और गवर्नर की मंजूरी की भी जरूरत होगी। सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। ऐसे में नए नक्शे को मंजूरी मिलना लगभग तय है। सरदन में नए विधेयक के पक्ष में 88 और विपक्ष में 52 वोट पड़े। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने नए नक्शे को अवांछित में चुनौती देने का कतई नहीं है। डेमोक्रेट्स ने आरोप लगाया कि नया नक्शा रिपब्लिकन पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है।

टेक्सास के रिपब्लिकनों ने खुलेआम कहा कि वे अपनी पार्टी के हित में काम कर रहे हैं। राज्य प्रतिनिधि टॉड स्टैटर, जिन्होंने औपचारिक रूप से नया नक्शा बनाने वाला विधेयक लिखा था, ने कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राजनेताओं को स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण उद्देश्यों के लिए जिलों का पुनर्निर्धारण करने की अनुमति दी है।

आईडीएफ ने शुरू किया गाजा पर कब्जा अभियान

यरुशलम, एजेंसी। इजरायल ने गाजा पट्टी पर कब्जा करने की अपनी अहम रणनीति के तहत बुधवार को युद्ध का अगला चरण शुरू कर दिया है। इसके साथ ही इजरायली सेना के जवान गाजा पट्टी में अंदर घुस गए। इजरायली सेना के मुख्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने घोषणा की कि इजरायल ने युद्ध का अगला चरण शुरू कर दिया है और सेना गाजा शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गई है। वहां विस्थापित निवासियों को दक्षिणी गाजा में स्थानांतरित करने की तैयारी चल रही है। आईडीएफ के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय चिंता पैदा हो गई है और फिलिस्तीनी राज्य के भविष्य पर बहस फिर से शुरू हो गई।

इजरायल की तरफ से यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब वार्ताकार मिस इजरायल और हमास के बीच 22 महीनों से जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए युद्धविराम की कोशिशों में लगा हुआ है। इस बीच, एक अहम रणनीति का खुलासा करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की कि वह गाजा शहर पर कब्जा करने की आईडीएफ की योजनाओं की समय सीमा कम कर रहे हैं। यह घोषणा रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर द्वारा पेरिस में कतर के अधिकारियों के साथ वार्ता पर चर्चा के एक दिन बाद की गई।

नहीं दे सकते पांच महीने : जब सुरक्षा कैबिनेट



ने पहली बार गाजा शहर पर कब्जा करने की मंजूरी दी थी, तब इजरायली अधिकारियों ने अनुमान जताया था कि इस योजना में पाँच महीने या उससे ज्यादा का समय लग सकता है लेकिन बुधवार को नेतन्याहू ने सेना को समय सीमा कम करने का निर्देश दिया है। बुधवार की शाम एक बयान में नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सेना को आतंकवादियों के अंतिम गढ़ों पर कब्जा करने और हमास को हराने की समय सीमा कम करने का निर्देश दिया है, जो गाजा शहर में आईडीएफ के आगामी हमले का संकेत है। नेतन्याहू ने दृष्टस से साफ कहा है कि

इसके लिए पांच महीने नहीं दे सकते।

सीजफायर प्रस्ताव पर भी नजर : हालाँकि पिछले कुछ दिनों में बंधकों की रिहाई के समझौते पर पहुँचने की गति तेज हुई है। बावजूद, इसके नेतन्याहू ने ऐसे प्रयासों को लगातार खारिज किया है और इस महीने की शुरुआत में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत योजना के बजाय गाजा पट्टी में लड़ाई तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि, उन्होंने युद्धविराम के नवीनतम प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है।

60,000 रिजर्व सैनिकों को तैनात करने का आदेश : दूसरी तरफ, जैसे-जैसे गाजा शहर पर बड़े पैमाने पर हमले के शुरुआती चरण जमीं पर अमल में आ रहे हैं, वैसे-वैसे इजरायल वहां सैन्य तैनाती बढ़ाता जा रहा है। उत्तरी गाजा के सबसे बड़े शहर, जिसके बारे में इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह हमास के अंतिम गढ़ों में से एक है, पर कब्जा करने के लिए सेना ने 60,000 रिजर्व सैनिकों को तैनात करने का आदेश दिया है। इसके अलावा 20,000 अतिरिक्त सैनिकों की सेवा अवधि बढ़ाने का भी फैसला किया गया है।

आईडीएफ की योजना की हो रही निंदा : इजरायली सुरक्षा बल की इस योजना की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर निंदा हो रही है, क्योंकि इससे इस आशका को बल मिल रहा है कि गाजा में मानवीय और भूखमरी का संकट और भी बदतर हो जाएगा और

आईडीएफ के विस्तारित सैन्य अभियान से शेष बंधकों की जान पर संकट बढ़ जाएगा। मानवाधिकार समूहों ने भी चेतावनी दी है कि गाजा में मानवीय संकट और भी बदतर हो सकता है। समूहों ने कहा कि गाजा में अधिकांश निवासी विस्थापित हो गए हैं, विशाल इलाके खंडहर में तब्दील हो गए हैं और लोगों पर अकाल का खतरा मंडरा रहा है।

इजरायली सैनिक अब हो रहे हताश : सीएनएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब दो साल से युद्ध लड़ रहे इजरायली सैनिक अब हताश होने लगे हैं। युद्ध का अंत नजदीक नहीं दिखने के कारण इजरायल के सैन्य प्रमुख ने सैनिकों पर बढ़ते बोझ की चेतावनी दी है, जिनमें से कई को गाजा में लड़ने के लिए कई बार बुलाया गया है। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने इस महीने की शुरुआत में सुरक्षा कैबिनेट को बताया था कि सेना को क्षति और थकान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नेतन्याहू और उनके गठबंधन सहयोगियों ने गाजा अभियान को आगे बढ़ाते हुए उनकी चिंताओं को खारिज कर दिया।येरुशलम के हिब्रू विश्वविद्यालय में अगम लैम्ब के एक नए सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग 40व सैनिक युद्ध के लिए थोड़े या काफी कम प्रेरित थे, जबकि 13व से थोड़े अधिक सैनिक युद्ध के लिए अधिक प्रेरित थे।

अमेरिका के मशहूर जज फ्रैंक कैप्रियो का निधन, दयालु जज के नाम से फेमस हुए

वाॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिका के मशहूर जज फ्रैंक कैप्रियो का बुधवार को निधन हो गया। वे 88 साल के थे। कैप्रियो लंबे समय से पैंक्रियाटिक कैंसर से लड़ रहे थे। उनके परिवार ने इंस्टाग्राम पर उनकी मौत की जानकारी दी। कैप्रियो अपने कोर्ट शो कांट इन प्रोविडेंस से दुनियाभर में मशहूर हुए। यह शो 2018 से 2020 तक चला और कई डेटाइटम एमी अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट हुआ। उनकी दया और इंसानियत भरे फैसलों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं। उन्होंने कई बार गरीब परिवारों के चालान माफ किए और लोगों को हैसला दिया।

सोशल मीडिया पर कैप्रियो के कई वीडियो वायरल : जज फ्रैंक कैप्रियो के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। उनके इंस्टाग्राम पर उनके 34 लाख फॉलोअर्स हैं। उनके वीडियो को ऑनलाइन अरबों बार देखा गया।

कैप्रियो ने रविवार को ही इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है और वे फिर से अस्पताल में हैं। उन्होंने लोगों से प्रार्थना करने की अपील की थी। कैप्रियो को लोग दुनिया का



सबसे दयालु जज कहते थे। उनका मानना था कि न्याय में दया और इंसानियत जरूर होनी चाहिए।

रोड आइलैंड में एक दिन के लिए इंडा आधा झुकाया : कैप्रियो का जन्म अमेरिका के रोड आइलैंड में हुआ था। रोड आइलैंड के गवर्नर डैन मैकी ने उन्हें राज्य का असली खजाना बताया। राज्य में उनके सम्मान में झंडे आधे झुका दिए गए हैं। उन्होंने लंबे समय तक म्युनिसिपल जज के तौर पर काम किया। 2023 में उन्होंने खुद बताया था कि उन्हें कैंसर है। इलाज के दौरान वे लगातार लोगों से जुड़े रहे और अपडेट देते रहे। कैप्रियो पारिवारिक जीवन में भी बेहद समर्पित थे। पतिवार ने कहा कि वे एक अच्छे पति, पिता, दादा और परदादा के रूप में याद किए जाएंगे।

भारत मूल्यवान साझेदार, मजबूत रिश्ते में खटास रणनीतिक आपदा: निक्की हेली

वाशिंगटन, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि भारत को चीन जैसा विरोधी नहीं, बल्कि एक मूल्यवान स्वतंत्र और लोकतांत्रिक साझेदार मानना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका भारत के साथ पिछले 25 वर्षों से बने संबंधों की रफ्तार रोकता है, तो यह एक रणनीतिक आपदा होगी।

निक्की हेली ने भारत और चीन के बीच एक मजबूत साझेदारी को बेहद आसान बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसका उदय स्वतंत्र दुनिया के लिए कोई खतरा नहीं है। इसके उलट, चीन की ताकत बढ़ना दुनिया के लिए चुनौती है, क्योंकि वह कम्युनिस्ट शासन के तहत चलता है।

अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी बन सकता है भारत : निक्की हेली ने अपने लेख में कहा कि भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी बन सकता है, जबकि चीन रूस से तेल खरीद कर प्रतिबंधों से बच रहा है और मास्को का सबसे बड़ा ग्राहक है। अमेरिका को



यह समझना होगा कि अगर एशिया में चीन का मुकाबला करना है तो भारत ही एकमात्र देश है जो यह संतुलन बना सकता है।

भारत में चीन की तरह बड़े पैमाने पर सामान बनाने की क्षमता : निक्की हेली ने आगे कहा कि भारत में इतनी क्षमता है कि वह चीन की तरह बड़े पैमाने पर सामान बना सकता है। इससे अमेरिका को अपनी सप्लाई

चेन चीन से हटाकर भारत में शिफ्ट करने में मदद मिलेगी। भारत कपड़े, सस्ते फोन और सोलर पैनल जैसे उत्पाद बड़े स्तर पर बना सकता है, जिन्हें अमेरिका खुद तुरंत या बड़े पैमाने पर नहीं बना सकता।

मध्य पूर्व में स्थिरता लाने में अहम साबित हो सकती है भारत की भूमिका : हेली ने आगे कहा कि भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और मध्य पूर्व में उसकी भूमिका उस क्षेत्र में स्थिरता लाने में अहम साबित हो सकती है, खासकर जब अमेरिका वहां सैनिकों और पैसों की संख्या कम करना चाहता है। भारत की भौगोलिक स्थिति चीन के व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के रास्तों पर दबाव डाल सकती है, जो किसी बड़े संघर्ष की स्थिति में चीन के विकल्प कम कर देगी।

भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था : निक्की हेली ने आगे कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही जापान को पीछे छोड़ देगा। भारत का उदय चीन की उस महत्वाकांक्षा को रोक देगा, जिसमें वह वैश्विक व्यवस्था को अपने हिस्सा से ढालना चाहता है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत मजबूत होगा, चीन की महत्वाकांक्षाएं घटेंगी।

अमेरिका-भारत की साझेदारी करने पर दोनों देशों के हित पूरे होंगे : निक्की हेली ने यह भी याद दिलाया कि भारत और चीन के बीच कई विवाद हैं, जिनमें 2020 का गलवां घाटी संघर्ष भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और भारत साझेदारी करते हैं तो दोनों देशों के हित पूरे होंगे और भारत चीन के खिलाफ ज्यादा मजबूती से खड़ा हो सकेगा। हेली ने चेतावनी दी कि अमेरिका-भारत के बीच व्यापार विवाद को अगर लंबा खींचा गया तो यह एक बड़ी और टाली न जा सकने वाली गलती होगी। चीन इस स्थिति का फायदा उठा सकता है।

अमेरिकी कोर्ट ने टुकड़ाई न्याय विभाग की मांग, वैंड जूरी दस्तावेज सार्वजनिक करने से किया इनकार

वाशिंगटन, एजेंसी।अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने जेफ्री एपरस्टीन की मौत के मामले में बुधवार को ट्रंप प्रशासन को एक बार फिर झटका दिया है। इसके तहत न्यायाधीश ने जेफ्री एपरस्टीन से जुड़े देह व्यापार मामले की ग्रैंड जूरी की सुनवाई के दस्तावेज (ट्रांसक्रिप्ट्स) सार्वजनिक करने की ट्रंप प्रशासन की मांग को खारिज कर दिया। इससे पहले दो अन्य जज भी इसी तरह की मांग को ठुकरा चुके हैं।

मामले में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश रिचर्ड बर्मन ने कहा कि इन ट्रांसक्रिप्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है जो जनता की जिज्ञासा को संतुष्ट कर सके। उन्होंने इसे ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। साथ ही कहा कि असल में एपरस्टीन से जुड़े करीब एक लाख पन्नों के दस्तावेज सरकार के पास हैं, लेकिन उन्हें अभी तक जारी नहीं किया गया है। न्यायाधीश ने ये भी कहा कि सरकार के पास असली और ठोस जानकारी है, लेकिन वह सिर्फ ग्रैंड जूरी की सीमित जानकारी जारी करवाना चाहती है, जो कि असल तथ्यों का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है।



ट्रंप प्रशासन ने की थी दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग : बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग की थी, ताकि यह दिखाया जा सके कि वे पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। ट्रंप खुद भी इस केस में नाम आने को लेकर

आलोचनाओं का सामना कर चुके हैं और उन्होंने चुनाव के दौरान सभी फाइलें जारी करने का वादा किया था। लेकिन जब उन्होंने कुछ दस्तावेज जारी किए, तो उनमें कुछ नया नहीं था, जिससे उनके समर्थकों में भी नाराजगी थी।

घिसलेन मैक्सवेल को लेकर भी जारी चर्चा जारी दूसरी ओर इस मामले में एपरस्टीन की सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल को लेकर भी चर्चा जारी है। मैक्सवेल फिलहाल फिलहाल 20 साल की सजा काट रही हैं। अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति उनसे पृच्छाछ करना चाहती है, लेकिन उनके वकीलों ने कहा है कि अगर उन्हें कानूनी सुरक्षा (इम्युनिटी) नहीं दी गई, तो वे बयान नहीं देंगे।

कौन थे जेफरी एपरस्टीन? गौरतलब है कि जेफरी एपरस्टीन एक अमीर फाइनेंसर थे, जिनपर कम उम्र की लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के गंभीर आरोप थे। वह 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में मृत पाए गए थे, जब उन पर मुकदमा चल रहा था। उनकी मौत को लेकर अब भी संदेह और साजिश की थ्योरी चलती रहती हैं। साथ ही उनकी मौत और केस से जुड़े कई दस्तावेजों को छिपाने के आरोपों को लेकर अमेरिका में कई लोग सरकार पर पर्दा डालने का आरोप लगाते रहे हैं।

क्या आपका बच्चा भी पढ़ने में करता है आनाकानी...

ये खास टिप्स अपनाएं और फिर देखें जादू

अगर आपका भी बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता तो ये टिप्स जरूर अपनाएं। इससे आपके बच्चे का पढ़ाई में फोकस भी बढ़ेगा और परफॉर्मेंस में भी सुधार होगा। कोरोना के बाद से ही हर माता-पिता की शिकायत है कि उनका बच्चा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाता। कई माता-पिता दिनभर बच्चों के पीछे लगे भी रहते हैं फिर भी उनका ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं जाता। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है लॉकडाउन के वक लंबे समय तक स्कूल का बंद रहना। इसके अलावा इसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं जैसे तनाव में होना, ओवरएक्टिंग, कंसंट्रेशन की कमी, थकान महसूस होना वगैरा-वगैर.. इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं, जिसे आप फॉलो करते हैं तो आपके बच्चे का पढ़ाई में मन तो लगेगा ही साथ ही उसकी ब्रेन पावर भी बढ़ेगी। आइए जानते हैं इसके बारे में।

इन टिप्स को अपनाकर बच्चों का फोकस बढ़ाएं
ब्रेन गेम्स खेलने दें-अपने बच्चे को पढ़ाई की तरफ फोकस करवाने के लिए माईड गेम का सहारा ले सकते हैं। ऐसा करने से उनका ध्यान फोन से हटेगा और बच्चे में एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलती है और पढ़ाई में भी मन लगता है। हालांकि खेलने की टाइमिंग का ध्यान जरूर रखें। साल 2015 की एक अध्ययन के मुताबिक 4715 लोगों को दिन में 15 मिनट और सप्ताह में 5 दिनों तक ब्रेन गेम्स खेलने के लिए कहा गया। शोध में पाया गया कि इससे उन लोगों के दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऐसे में अपने बच्चे को चेंस, सुडोको, प ज ल, स्क्रैबल जैसे गेम्स खिलाएं।

वृक्षासन करावाएं-
बच्चे में एकाग्रता बढ़ाने के लिए आप वृक्षासन का भी सहारा ले सकते हैं। इस योग को करने से दिमाग की एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलती है। एक पैर पर बैलेंस बनाने से दिमाग को संतुलन और स्थिरता मिलती है। जब दिमाग में संतुलन और कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पढ़ाई में भी काफी मदद मिलेगी।

शारीरिक बल वाला खेल खेलने दें-
ऐसा ना हो कि बच्चे सिर्फ दिन भर मोबाइल फोन में ही घुसे रहें इससे भी उनके कॉन्संट्रेशन पर असर पड़ता है। आप बच्चे को एक घंटा बाहर मैदान में ले जाकर खेलने दें या तो बच्चे साइकिल चलाएं या फिर कोई आउटडोर गेम खेलें, जिससे शारीरिक विकास हो। शारीरिक बल लगे। 40 से 50 मिनट ऐसा करना काफी है। पोषक तत्वों की कमी ना होने दें-ध्यान रहे कि आपके बच्चे के खाने की

घरेलू उपाय हैं बेहद काम के, दूर होंगी स्किन तकलीफ



1 यदि आपको चुभती-जलती घमौरियों ने परेशान कर रखा है, उसमें लगातार खुजली, जलन बनी हुई है तो आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। घमौरियां दूर करने का यह बेस्ट घरेलू नुस्खा है। इसके लिए 1 बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 1 चम्मच गुलाब जल डालकर मिक्स करें। इस पेस्ट को घमौरियों पर अप्लाई करें। मुल्तानी मिट्टी ठंडा प्रभाव करता है, जिससे जलन, खुजली कम होती है। साथ ही मुल्तानी मिट्टी में एंटीमाइक्रोबियल गुण भी होते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया आदि के कारण स्किन संबंधित समस्याओं को नहीं होने देते।

2 यदि आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो उसका जेल एक कटोरी में निकाल लें। इसे जहां-जहां घमौरियां हुई हैं, वहां अच्छी तरह से अप्लाई करके आधे घंटे के लिए छोड़ दें। एलोवेरा जेल स्किन के लिए बेस्ट होता है। यह त्वचा को सॉफ्ट बनाता है। आप रात में सोने से पहले भी एलोवेरा जेल अप्लाई करके सो सकते हैं और सुबह उठकर ठंडे पानी से त्वचा को साफ कर सकते हैं। एक से दो दिन इस जेल को लगाकर देखें, घमौरियां गायब हो जाएंगी।

3 घमौरियों से परेशान हैं तो इस पर आइस क्यूब पैक रख सकते हैं। इसके लिए एक कपड़े में 5-6 बर्फ के टुकड़ों को डालकर बांध लें और इसे घमौरियों वाली जगह पर रखें। जलन, खुजली, रेड रेशेज सभी समस्याएं धीरे-धीरे कम होने लगेंगी।

4 नीम की पत्तियों से भी घमौरियों का इलाज संभव है। आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है तो 15-20 पत्तियां लाकर इसे साफ कर लें। आधे लीटर पानी को एक बर्तन में डालें। इसमें इन पत्तियों को डालकर गैस पर उबलने के लिए रख दें। जब नीम वाला पानी ठंडा हो जाए तो इससे प्रभावित त्वचा को साफ करें। घमौरियां में होने वाली जलन, खुजली कम हो जाएगी।

5 दही का इस्तेमाल हर घर में डेली होता है। क्या आप जानते हैं कि दही लगाने से भी घमौरियां कम हो सकती हैं? नहीं पता, तो एक बार इस नुस्खे को घमौरियों पर आजमाकर देखें। स्किन के लिए दही वैसे भी फायदेमंद होती है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी आपको नहीं होगा। दही को अच्छी तरह से मिक्स करके प्रभावित त्वचा पर अप्लाई करें। थोड़ी देर ऐसे ही रहने दें फिर ठंडे पानी से स्किन को साफ कर लें। दही में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं, जो बैक्टीरिया का सफाया करते हैं।



थाली में पोषक तत्वों की कमी ना हो ऐसा होने से भी एकाग्रता करने में मुश्किल होती है। बच्चों की डाइट में फल सब्जियां, अंडे, दूध आदि को शामिल करें। इसके अलावा बच्चे की डाइट में और टमाटर शकरकंद, कद्दू, गाजर, पालक दही भी होना चाहिए। बच्चों को तेल और मिर्च वाले खाने से दूर रखें, इससे आलस बढ़ता है।

तनाव से दूर रखें-
अगर घर में किसी तरह का तनाव चल रहा है तो इससे बच्चे को दूर रखें। ऐसा होने से भी बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बच्चे को कुछ दिनों पर कहीं घुमाने ले जाएं। उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रख सकें। यह भी ध्यान रखें कि बच्चे की नींद ठीक से पूरी हो जाए क्योंकि एकाग्रता के लिए ब्रेन का रिचार्ज होना भी बहुत जरूरी है।

कबूतरों की बीट से गंदा हो गया बालकनी का फर्श

दिल्ली और मुंबई सहित कई शहर ऐसे हैं, जहां कबूतरों की संख्या बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग इनकी मौजूदगी से काफी परेशान रहते हैं। दरअसल, कबूतर घरों की छत और बालकनी में अपना आशियाना बना लेते हैं और अपनी बीट से इन जगहों पर गंध फैलाते हैं। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार छत और बालकनी से इनकी बीट को साफ करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप चाहें तो स्टैप बाई स्टैप कुछ आसान तरीके इस्तेमाल करके कबूतरों के मल (Pigeon poop) को आसानी से साफ कर सकते हैं।

खाना-खजाना

रायते में कर लें ये काम फिर स्वाद ही नहीं बढ़ेगा, डबल हेल्दी भी हो जाएगा!

रायता खाने का अपना ही मजा है। ये खाने का स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही शरीर को ठंडक भी पहुंचता है। ये पेट के लिए भी अच्छा होता है। पाचन शक्ति को भी बढ़ावा देता है। यूं तो रायता की कई सारी वैरायटी है जैसे मिक्स वेज रायता, खीरे का रायता, बूंदी रायता.. लेकिन प्याज के रायते की बात ही अलग है। यह टेस्टी भी होता है और फायदेमंद भी होता है ये लंच डिनर या किसी भी वकत रोटियां चावल के साथ खाया जा सकता है। इसका टेस्ट जो बच्चों से लेकर बड़ों बुजुर्गों सबको पसंद आता है तो चलिए जानते हैं प्याज का रायता

बनाने का आसान तरीका
सामग्री : प्याज-बारीक कटे 2 दही -2 कप लाल मिर्च पाउचर हरी मिर्च बारीक कटी -1 रायता मसाला- 1 टीस्पून जीरा- 1 चम्मच चीनी- 1/4 टीस्पून हरा धनिया- 2 टेबलस्पून तेल -1 टेबलस्पून नमक- स्वादअनुसार

रायता बनाने की विधि
प्याज को बारीक काट लीजिए, इसके बाद हरी मिर्च और हरा धनिया भी बारीक काट लें। अब एक बर्तन में दही और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से फेंट लें। दही को तब तक फटना है जब तक के यह बिल्कुल स्मूद और पतला ना बन जाए। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल डालें और उसमें मीडियम आंच पर गर्म करने करने के लिए रख दें।

तेल गर्म हो जाए तो उसमें जीरा और कटी हरी मिर्च डालकर कुछ सेंकंड तक भुनें। इसके बाद प्याज डालकर धीमी आंच पर हल्का सा भूनें अब कड़ाही में फेंटा हुआ दही डाल कर पकाएं 1 से 2 मिनट बाद दही में लाल मिर्च पाउडर, चीनी, रायता मसाला, नमक डालकर घोलते हुए मिक्स कर लें प्याज का रायता खाने के फायदे प्याज और दही दोनों में पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। दही में विटामिन बी5, विटामिन b12, पोटेशियम, राइबोफ्लेविन, आयोडीन, जिंक, फास्फोरस पाया जाता है। वहीं प्याज में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी के अलावा फोलिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फाइबर होते हैं। एक कटोरी प्याज का रायता खाने से यह सारे पोषक तत्व आपके शरीर में पहुंच जाते हैं।



एलोवेरा जूस से स्किन की लौट आएगी पुरानी चमक

ब्लड शुगर भी रहेगी कंट्रोल! 4 गज़ब के फायदे रखेंगे हेल्दी

एलोवेरा में पोषक तत्वों का भंडार मौजूद है। स्किन को चमकदार बनाने के साथ ही ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी एलोवेरा मददगार होता है। इसके गजब के फायदे जानकर आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। एलोवेरा एक ट्रॉपिकल प्लांट है और इसमें प्रचुर मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक ओरल हेल्थ के लिए भी एलोवेरा का इस्तेमाल काफी लाभकारी हो सकता है। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में भी एलोवेरा जूस काफी लाभकारी हो सकता है।

से होने वाले नुकसान से भी बचाती हैं। एलोवेरा जूस में पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो कि शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। एलोवेरा जूस का सेवन शरीर को ऊर्जा से भी भर देता है

डाइजेशन
हर दूसरे व्यक्ति को पेट संबंधी समस्याएं होती हैं। खासतौर पर पाचन से जुड़ी परेशानियां अक्सर देखने को मिलती हैं। एलोवेरा जूस में Anthraquinone Glycosides होता है जिसमें लेक्सेटिव प्रभाव होता है जो कि कब्ज की समस्या से राहत दिला सकता है। कब्ज की समस्या में सुधार होने पर धीरे-धीरे डाइजेशन में भी सुधार आता है।

ओरल हेल्थ
दांतों और ओरल हेल्थ की समस्याओं से ज्यादातर लोग जुझते नजर आते हैं। कुछ रिसर्चों में सामने आया है कि ओरल हेल्थ को बेहतर रखने में एलोवेरा का जूस कारगर हो सकता है। एलोवेरा जूस और इससे बनने वाले माउथ वॉश में काफी एंटी-बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि दांतों से जुड़ी समस्याओं से राहत देने में मददगार हो सकती हैं।



रिकन हेल्थ
एलोवेरा जूस में मौजूद प्रॉपर्टीज स्किन को हेल्दी रखने के लिहाज से बेहद फायदेमंद होती हैं। जलन या फिर किसी भी तरह के स्किन डिसऑर्डर में एलोवेरा जूस का सेवन काफी लाभकारी हो सकता है। एलोवेरा जूस को पीने के साथ ही अगर एलोवेरा जूस को स्किन पर लगाया जाए तो इससे भी स्किन चमकदार बनने में मदद मिलती है। कुछ रिसर्च में सामने आया है कि एलोवेरा जूस का सेवन स्किन इलास्टिसिटी बेहतर बनाने के साथ ही रिकल्स को भी घटाता है।

डायबिटीज
शुगर पेशेंट्स के लिए एलोवेरा जूस का सेवन लाभकारी हो सकता है। अब तक हुई रिसर्च में ये पाया गया है कि प्री-डायबिटीज की स्थिति में एलोवेरा जूस पीने से फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बेहतर बनाने में मदद मिलती है। हालांकि अब भी इसे लेकर और डेटा और रिसर्च होने की जरूरत है जिससे किसी ठोस नतीजे पर पहुंचा जा सके।

एंटी-ऑक्सीडेंट्स रिच
एलोवेरा प्लांट एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। इसमें एंटी-इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होता है जो कि शरीर को फ्री रैडिकल्स

करके मिक्सचर बना लें। फिर इस क्लीजिंग लिक्विड को बीट वाली जगहों पर अच्छे से स्मै कर दें और तकरीबन पंद्रह मिनट के लिए ऐसे **पलोरा क्लीनर से क्लीन करें** अब क्लीजिंग के नेक्स्ट स्टेप में फ्लोर क्लीनर की मदद से आप बालकनी या छत को साफ करें। इसके लिए आप फ्लोर क्लीनर को पहले बालकनी या छत पर डालकर पंद्रह मिनट के लिए छोड़ दें। फिर ताड़ वाली झाड़ू को मदद से राइड कर फर्श को साफ करें। **माइक्रोफाइबर कपड़े से करें साफ:** फ्लोर क्लीनर से फर्श की सफाई

करने के बाद जरूरी है कि फर्श पर अच्छी तरीके से पोछा लगाया जाये। इसके लिए आप किसी डिस्पोजल माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें और बालकनी और छत के फर्श को पोंछ कर सुखा लें। इसके बाद साफ पानी की मदद से एक बार फिर से फर्श की धुलाई कर लें। **इन बातों का भी रखें ख्याल** पिजन पूष साफ करते समय इस तरह के शुज और स्लीपर का इस्तेमाल करें जो फिसलने वाले न हों। साथ ही सफाई के समय बालकनी और छत की रेलिंग को अच्छे से थाम कर रखें।

स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए इन सब्जियों को करें डाइट में शामिल

जंगली पालक: जंगली पालक में कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करती है। यह क्लीजिंग, गैस अपच जैसी समस्याओं से छुटकारा भी दिलाती है।

सिंहपर्णी: सिंहपर्णी में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह पाचनतंत्र को मजबूत

मुंबई में पर्युषण महापर्व का शुभारंभ

मुंबई में पर्युषण महापर्व के अवसर पर अटलांटिक प्लाज़ा, दादर में चौवीहार हाउस का शुभारंभ



पर्युषण महापर्व के दौरान दादर स्थित अटलांटिक प्लाज़ा में चौवीहार हाउस का शुभारंभ किया गया। चौवीहार हाउस का उद्घाटन श्री जैन धार्मिक शिक्षण संघ के उपाध्यक्ष श्री संजय शाह, महिला विभाग उपाध्यक्ष श्रीमती अल्पा संजय शाह, चेयरमैन हरेशभाई पटेल, उपाध्यक्ष भावेशभाई कोटक, सेक्रेटरी मुकेशभाई कोटक तथा प्रगति ग्रुप के नानजीभाई गाला और मनीष सावंत (विधायक)द्वारा दीप

प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर श्री संजय शाह और श्रीमती अल्पा संजय शाह का समिति द्वारा सम्मान भी किया गया। चौवीहार हाउस में प्रतिदिन लगभग ८०० से ९०० जैन श्रद्धालु चौवीहार का लाभ लेते हैं। यहां एकासन, व्यासन तथा उबला हुआ पानी उपलब्ध कराया जाता है। चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुके इस चौवीहार हाउस में सभी उपवास करने वाले श्रद्धालुओं को प्रभावना स्वरूप सम्मानित किया जाता है।

यह चौवीहार हाउस रविवार और संवत्सरी के दिन बंद रहेगा। यहां से पशुपक्षी पांचरपोल सहायता तथा अनेक सामाजिक सेवा कार्य भी संचालित किए जाते हैं। इस अवसर पर संदीपभाई दोशी, नितिनभाई छोट्टा, चेतन नितिनभाई शेट, खिलनभाई, मनीषभाई रामभिया, विनोदभाई वीरा, धीरजभाई मोरवी, ममता आर्ट, नानजीभाई गाला मनीष सावंत (विधायक) तथा जैन समाज के कई सदस्य उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा

दुर्ग। मुख्यमंत्री के विष्णुदेव साय ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागयुक्त एवं कलेक्टरों की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का आयोजन, लोक निर्माण विभाग की सड़कों हेतु भू-अर्जन प्रकरणों, राजस्व विभाग के ई-कोर्ट न्यायालयों में प्रकरणों का त्वरित निराकरण, एग्रीस्टेक के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन एवं किसान आईडी निर्माण तथा खरीफ फसलों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण 15 अगस्त से 30 सितम्बर तक पूर्ण करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के आयोजन के संबंध में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रत्येक जिले में रजत महोत्सव को गरिमामय और जनसहभागिता के साथ आयोजित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि



कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार करते हुए प्रत्येक विभाग द्वारा एक-एक सप्ताह स्थानीय त्यौहार एवं विशेष अवसरों पर कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक 'सेवा पखवाड़ा' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो रजत जयंती समारोह का ही एक महत्वपूर्ण भाग होगा। राजस्व विभाग के अंतर्गत संचालित ई-कोर्ट प्रणाली पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टरों से कहा कि लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ शीघ्र

निराकरण किया जाए। इससे न केवल आम नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति भी आएगी। साथ ही उन्होंने संभागीय आयुक्त न्यायालयों में न्यायालयीन प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण करने को कहा। इस दौरान कृषि विभाग की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ एग्रीस्टेक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए और उनकी किसान आईडी बनाई जाए,

जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल सके। कोई भी किसान इससे वंचित न हो इसका विशेष ध्यान रखे। मुख्यमंत्री ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण अभियान पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि यह सर्वेक्षण 15 अगस्त से आरंभ कर 30 सितम्बर 2025 तक पूर्ण किया जाए। सर्वेक्षण का कार्य सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध होना चाहिए, जिससे भविष्य में किसानों को फसल बीमा, मुआवजा और अन्य योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने सभी संभागयुक्तों एवं कलेक्टरों से कहा कि विकास कार्य और जनसेवा से जुड़े कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं। जिला कार्यालय दुर्ग स्थित एनआईसी कक्ष में संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर, कलेक्टर अभिजीत सिंह और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अगस्त में 3 दिन एवं सितम्बर में 2 दिन नहीं बेच सकेगे मांस-मटन

दुर्ग। अगस्त व सितंबर माह के 5 दिन दुर्ग शहर सीमा क्षेत्र अंतर्गत में मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर नगर निगम ने आदेश जारी किया है कि 20 अगस्त (पर्युषण पर्व के पहले दिन), 26 अगस्त (गणेश चतुर्थी) और 27 अगस्त (पर्युषण के आखिरी दिन) सहित 3 सितंबर डोला ग्यारस व 6 सितम्बर अनंत चतुर्दशी को पूरे नगर निगम क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह और सभी मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। निगम की स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रा ने बताया कि यह आदेश शासन के नगरीय प्रशासन व विकास विभाग के निर्देश पर जारी किया गया है। इन तिथियों पर जोन स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखेंगे। वे देखेंगे कि प्रतिबंध का सख्ती से पालन हो सके। महापौर अलका बाब्रमार व आयुक्त सुमित अग्रवाल ने चेतावनी दी है कि पावन पर्वों के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गवाह को धमकाने गए आरोपी की हुई हत्या

- हत्या के आरोपी पिता पुत्र हिरासत में
- जमानत पर जेल से छूटकर आया था मृतक
- आरोपी के चाकू से ही की उसकी हत्या



घर पहुंच गया और उसकी पत्नी और सुधाकर मोहरे को धमकाने लगा कि वह उसके खिलाफ किसी प्रकार की दिया जिससे मौके पर ही जमानत पर छोटे सोनू बाबू की मौत हो गई। फ्लिहाल पुलिस ने दोनों आरोपी पिता पुत्र को हिरासत में ले लिया है। मामले की विवेचना की जारी है।

का चाकू जमीन पर गिर गया तब सुधाकर मोहरे के पुत्र ने उसी चाकू से सोनू रेडी पर जानलेवा हमला कर दिया जिससे मौके पर ही जमानत पर छोटे सोनू बाबू की मौत हो गई। फ्लिहाल पुलिस ने दोनों आरोपी पिता पुत्र को हिरासत में ले लिया है। मामले की विवेचना की जारी है।

अग्रवाल महिला कल्याण समिति ने मनाया श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व

बच्चों और महिलाओं ने प्रस्तुत किया सांस्कृतिक कार्यक्रम

मंदिर परिसर श्री कृष्ण के जयकारों और भजनों से गुंज उठा
अग्रसेन भवन सेक्टर 6 में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए लोग



भिलाई। भिलाई सेक्टर-6 स्थित अग्रसेन भवन में अग्रवाल महिला कल्याण समिति द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भव्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन किया गया। यह आयोजन समिति द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत सामाजिक के वरिष्ठजनों द्वारा विधिवत

पूजा-अर्चना के साथ की गई। इस दौरान समाज के लोगों ने बद्ध-चढ़ कर भाग लिया और पूरे आयोजन स्थल को भक्तिमय बना दिया। इस विशेष आयोजन में कन्हा जी का नौका विहार, छप्पन भोग, और कान्हा की आकर्षक झांकी सभी के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही। बच्चों और महिलाओं द्वारा

प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समां बांध दिया। रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया और हर कोई कृष्ण भक्ति में डूबता नजर आया, कार्यक्रम के दौरान संपूर्ण परिसर श्री कृष्ण के जयकारों और भजनों से गुंज उठा, जिससे क्षेत्र में एक अलौकिक और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला।

अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का करेंगे प्रयास

- विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने किया कैबिनेट मंत्री का स्वागत
- शुभकामनाएं देने लोगों का लगा रहा तांता



भिलाई। दुर्ग विधायक गजेन्द्र यादव के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र में आते ही कार्यकर्ताओं एवं उनके प्रशंसकों ने उनका भव्य स्वागत किया और सफ़ाई हाउस में शिक्षा विभाग एवं विधि उद्योग विभाग सहित निगम व अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत अभिनंदन किया। इसी बीच मीडिया से मुखातिर होते हुए

कैबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसे निष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा से पूरा करना जहां तक शिक्षा की बात है तो आने वाले समय में सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता पर ही फोकस रहेगा साथ ही लोकल फॉर ओकल में

ध्यान केंद्रित कर गांवों व शहरों में विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित सामनों एवं उपायों का उपयोग कर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर लोगो को स्वरोजगार दे कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।

सिद्ध बाबा मंदिर परिसर में लायंस क्लब मनेन्द्रगढ़ प्राइड ने लगाए गुलमोहर के पौधे



मनेन्द्रगढ़। लायंस क्लब मनेन्द्रगढ़ प्राइड द्वारा बुधवार को सिद्ध बाबा मंदिर परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्लब सदस्यों ने गुलमोहर के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। क्लब अध्यक्ष लायन पूनम सिंह ने कहा कि वृक्ष जीवन का आधार हैं, पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इस तरह के प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरा-भरा वातावरण सुनिश्चित करेंगे।

सदस्यों ने पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण का संकल्प भी लिया। लायंस क्लब समय-समय पर ऐसे सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यक्रमों के जरिए जनजागरूकता लाने का प्रयास करता है। कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों ने पौधों की देखभाल एवं संरक्षण का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वृक्ष जीवन का आधार हैं और हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस मौके पर क्लब की कई पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

होलसेल कपड़ा मार्केट राजनांदगांव ही नहीं, छग, महाराष्ट्र के लिए सशक्त केंद्र बनेगा-खूबचंद पारख

- शहर के सत्यम परिवेश में कपड़ा व्यापार को लेकर होलसेल मार्केट की शुरुआत हुई



राजनांदगांव। शहर के पुराना गंज चौक में लगभग 80 दुकानों के साथ बने अत्याधुनिक होलसेल क्लॉथ मार्केट सत्यम परिवेश का भव्य लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन की 20 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश संरक्षक खूबचंद पारख ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पारख ने कहा कि यह होलसेल कपड़ा मार्केट न केवल राजनांदगांव के व्यापार जगत के लिए बल्कि सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ और पड़ोसी महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के लिए भी एक नया और सशक्त व्यापारिक केंद्र साबित होगा। उन्होंने कहा कि व्यापार और उद्योग किसी भी शहर की प्रगति की रीढ़ होते हैं और इस मार्केट का निर्माण निश्चित रूप से स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई

दिशा देगा। उन्होंने उद्घारण देते हुए बताया कि जिस प्रकार रायपुर के पंडरी कपड़ा मार्केट और दुर्ग के पुलाव कपड़ा मार्केट ने वर्षों तक व्यापारी गतिविधियों को अपनी ओर आकर्षित किया और पूरे प्रदेश के व्यापार जगत में अपनी पहचान बनाई उसी प्रकार अब राजनांदगांव की कपड़ा मंडी भी पुनः अपनी खोई हुई पहचान को हासिल करेगी। पारख ने आगे कहा कि इस मार्केट के निर्माण से लाभ केवल कपड़ा व्यापारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा। बल्कि इसका सीधा सकारात्मक असर नगरवासियों, छोटे व्यापारियों, परिवहन सेवा प्रदाताओं और सहायक व्यवसायों पर भी पड़ेगा। रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और शहर में व्यापारिक गतिविधियों की चहल-पहल और अधिक बढ़ेगी। उद्योगपति सुनील मूंदड़ा ने कहा कि वे देश-विदेश घूमते रहते हैं पर

राजनांदगांव का यह जो कपड़ा मार्केट है वैसे देश में कहीं नहीं देखा विदेश में जरूर है ऐसा मार्केट है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष कमलेश बैद ने कहा कि छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स हमेशा व्यापारियों के साथ खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा। कपड़ा व्यापारी संघ हमारे संगठन का अभिन्न हिस्सा है। वहीं पूर्व महापौर नरेश डाकलिया ने कहा कि ऐसे ही सामूहिक रूप से ज्वेलरी बाजार किराना बाजार भी आ सकते हैं। क्योंकि कॉलोनाइजर ने 100 फीट चौड़ा मुख्य मार्ग बना कर दिया है। इससे यातायात की समस्या आने वाले कई वर्षों तक उत्पन्न नहीं होगी। उक्त अवसर पर मुख्य रूप से राजेंद्र गोलाख, श्रीकिशन खंडेलवाल, जानचंद बाफना, भावेश बैद, विनोद डहड, भीम धनवानी, आलोक बिंल, अमर लालवानी, तरुण लहरवानी, संजय जैन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, होलसेल क्लॉथ मार्केट सत्यम परिवेश के अध्यक्ष जवरचंद छाजेड़, उपाध्यक्ष दिनेश खण्डेलवाल, उपाध्यक्ष संतोष ओस्तवाल, कोषाध्यक्ष सुभाष खण्डेलवाल, सचिव ऋषभ टाटिया, सह सचिव राधेश्याम डागा आदि उपस्थित रहे।

संभाग स्तरीय कार्यालयों में शीघ्र ई-ऑफिस प्रक्रिया होगी प्रारंभ संभाग आयुक्त ने संभाग स्तरीय अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक



दुर्ग। दुर्ग के संभाग आयुक्त एसएन राठौर ने आज संभाग आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभागवार समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा की। संभाग आयुक्त राठौर ने कहा कि शासन की गुड-गवर्नेंस नीति के तहत दुर्ग संभाग के अंतर्गत सभी संभाग स्तरीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने संभाग प्रमुख अधिकारियों को ई-ऑफिस की प्रक्रिया के तहत कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिनस्थ कर्मचारियों को भी प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षित करने कहा। संभाग आयुक्त ने उपायुक्त को अधिकारियों और उनके अधिनस्थ कर्मचारियों के लिए शीघ्र संभाग स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करने को कहा। संभाग आयुक्त ने स्वच्छ छत्तीसगढ़ मिशन की समीक्षा करते हुए नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के अधिकारी को

शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में सॉलिड-लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने निर्देशित किया। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में मौका निरीक्षण करने उपायुक्त को निर्देशित किया। मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु कार्ययोजना की समीक्षा के दौरान पुलिस, उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग को रैली आदि का संयुक्त आयोजन कर विद्यार्थियों के माध्यम से जन-जागरूकता लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रैली में विद्यार्थियों की भागीदारी से वे स्वयं नशे के दुष्परिणाम से अवगत होंगे। संभाग आयुक्त ने स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने में सतर्कता

पूर्वक कार्यवाही करने कहा। संभाग आयुक्त ने संभाग के सभी पंचायतों में सहकारी समिति गठन की समीक्षा के दौरान मछुआ एवं दुग्ध समिति को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अब तक 1106 ग्राम पंचायत को समिति गठन के संबंध में कवर कर लिया गया है। बैठक में संभाग आयुक्त कार्यालय के प्राप्त पत्रों के निराकरण हेतु विभिन्न कार्यालयों को प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही की समीक्षा भी की गई। इस अवसर पर उपायुक्त (राजस्व) पदुमलाल यादव, उपायुक्त (विकास) संतोष ठाकुर सहित समस्त विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

निगम का बड़ा एक्शन आज फिर चार बकायादारों के नल कनेक्शन काटे गए, टैक्स वसूली में निगम का एक्शन मोड, बकायादारों में मची खलबली

आयुक्त सुमित अग्रवाल की चेतावनी, टैक्स नहीं चुकाया तो होगी सख्त कार्रवाई, लंबे समय से टैक्स बकाया, निगम ने कस लिया शिकंजा

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग राजस्व वसूली को लेकर लगातार सख्ती दिखा रहा है। आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर मंगलवार को राजस्व विभाग की टीम ने बड़े बकायादारों पर शिकंजा कसते हुए कार्रवाई की। टीम ने चार ऐसे घरों के नल कनेक्शन काट दिए जिन्होंने वर्षों से टैक्स जमा नहीं किया था। इस कार्रवाई के दौरान निगम की टीम वार्ड 2 राजीव नगर, वार्ड 5 मरार पारा, वार्ड 6 ठेठवार पारा और वार्ड 42 कसारीडीह क्षेत्र पहुंची। टीम ने मौके पर जाकर बकाया करदाताओं को अंतिम चेतावनी देने के बाद उनके नल कनेक्शन काट दिए।

इन बकायादारों पर हुई कार्रवाई- 1. बुधारू क्षीमर पिता केजूर राम, वार्ड 2 राजीव नगर डूब वर्ष 2010 से 2025-26 तक बकाया टैक्स राशि 49,390। 2. लता बाई पति सुंदर लाल सोनी, वार्ड 5 मरार पारा -वर्ष 2004 से



2025-26 तक बकाया टैक्स राशि 84,720। 3. अशोक कुमार शर्मा पिता मोहन प्रसाद शर्मा, वार्ड 6 ठेठवार पारा - वर्ष 2011 से 2025-26 तक बकाया टैक्स राशि 57,560। 4. अनंत राम साहू पिता रतन लाल साहू, वार्ड 42 कसारीडीह - वर्ष 2013



2025-26 तक बकाया टैक्स राशि 57,989। आयुक्त की सख्त चेतावनी- आयुक्त सुमित अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि निगम की वसूली अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा जो लोग वर्षों से टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई



होगी। नागरिकों को समझना होगा कि टैक्स की राशि से ही शहर का विकास और सुविधाओं का संचालन होता है। निगम बकाया करदाताओं को बिल्कुल भी बख्खाने वाला नहीं है। असर और संदेश-इस कार्रवाई के बाद

इलाके में संदेश गया कि नगर निगम अब किसी भी तरह की लापरवाही या टालमटोल बर्दाश्त नहीं करेगा। नियमित करदाता नागरिकों ने भी इस कदम का स्वागत किया और कहा कि इससे टैक्स जमा करने वालों और न करने वालों के बीच समानता का माहौल बनेगा।

प्रदेश अध्यक्ष डॉ. निरेंद्र साहू से पूर्व उपाध्यक्ष चंद्रिका साहू ने की सौजन्य भेंट



रायपुर। प्रदेश साहू समाज के निर्विरोध नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. निरेंद्र साहू से समाज की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रिका साहू ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने नवचयनित अध्यक्ष को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। चंद्रिका साहू ने कहा कि प्रदेश साहू संघ ने इस बार जो कदम उठाया है, वह ऐतिहासिक और अनुकरणीय है। समाज ने महंगे चुनावी प्रक्रिया से ऊपर उठकर एकता और संगठन की मिसाल पेश की है। निर्विरोध चुनाव से सभी पदाधिकारियों का चयन होना पूरे समाज के लिए गर्व का विषय है। भेंटवार्ता के दौरान उन्होंने सामाजिक व संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा की। साथ ही सुझाव दिया कि जिला से लेकर स्थानीय स्तर तक भी इसी प्रकार निर्विरोध चुनाव कराने की परंपरा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।